(Shri Madhusudan Vairale)

Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Public Undertakings :-

(i) Eighty-fifth Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Sixty seventh Report of the Committee on Hindustan Antibiotics Limited.

(ii) Eighty-sixth Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Seventy-fourth Report of the Committee on Mazagon Dock Limited Shipbuilding.

12.23 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported glut of potatoes in the country resulting in sharp fall in their prices causing sufferings to farmers.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि व अपना वक्तव्य दें :

"देश में आलू की कथित अत्यधिक पैदावार, जिसके परिणामस्वरूप इसके मूल्यों में बहुत गिरावट आई है, जिससे किसानों को हानि उठानी पड़ रही है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : Sir the production of Potatoes in the country has increased considerably in the last few years. It was about 83 lakh tons in 1979-80 and has gone upto 101 lakh tons in 1982-83. Uttar Pradesh is leading in production of potatoes followed by West Bengal and Bihar. These three States account for more than three-fourths of the country's production of potatoes. According to the estimates of the State Government of Uttar Pradesh, production in the year 1983-84 is likely to be more than 50 lakh tons against last year's production of around 45 lakh tons.

2. Price of potato was remunerative throughout the country till the middle of March, 1984. It still remains so in most parts of the country. However, reports indicate sudden slump in prices in some parts of Uttar Pradesh in the last week of March, 1984 due to heavy arrivals in the market.

3. The Government took precautionary steps in time. A Close watch was kept on the price situation. NAFED and U. P. Cooperative Marketing Federation were asked to keep in readiness to take prompt action to stabilise the price as and when necessary. A minimum support price of Rs. 50 per quintal for fair average quality potato has been agreed upon. The matter was taken up with the Ministry of Railways for the allotment of wagons. It has been reported by the Government of Uttar Pradesh that the railway authorities made sufficient number of wagons available for quick movement of potatoes to consuming areas. The Reserve Bank of India was requested to make adequate credit available to the State Government and purchasing agencies for the price support operations.

4. As soon as the Government received the report of sudden decline in prices, NAFED was requested to enter the market. Officers of NAFED have already visited the area and they have been directed to make purchases in Uttar Pradesh at a support price of Rs. 50/- per quintal. NAFED will keep close liaison with the State agencies to organise the support operations. The Government of Uttar Pradesh has also directed there Cooperative Marketing Federation to start purchases at the minimum support prices.

5. Situation is under close watch. A Control Room has been set up in the Ministry of Agriculture which is in constant touch with the State Governments. Let me assure the House that the Government will take all necessary steps to protect the interests of potato growers by ensuring reasonable prices of potato to them.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि राज्य मन्त्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य को देखने से ऐसा लगता है कि हमारी सरकार पूरे तरीके से किसानों की सुरक्षा करने में, उन की उपज के मूल्य निर्धारण में और उनके सामने जो अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यह केवल वक्तव्य मात्र है। यों तो सभी फसलों के लिए, लेकिन यहां विशेष रूप से आलू का जिक्र हो रहा है, इसलिए आलू के किसानों की रक्षा करने के मामले में सरकार पूरी तरह से असफल रही है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आदि देश के 10-12 ऐसे प्रान्त हैं जहाँ आलू की खेती बहुत अच्छी होती है और पिछले दशक से हमारे देश में आलू की खेती उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। आज से दस साल पहले हमारे यहां आलू 70 लाख मीट्रिक टन पैदा होता था, लेकिन इस वर्ष आलू का उत्पादन करीब 110 लाख मीट्रिक टन हुआ है।

12.27 hrs.

(MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*).

पूरे देश का 50 प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश में होता है। उपाध्यक्ष जी, आलू की फसल और इसके उत्पादन में लगे किसानों का दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार ठीक ढंग से या जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है। वैसे हर प्रमुख फसल जैसे कपास, गेहूं, गन्ना, धान आदि का पिछला 10-20 वर्षों का इतिहास देखें तो कोई न कोई कठिनाई, कोई न कोई समस्या, इन फसलों के उत्पादन में होती रही हैं। पिछले दशक में आलू की फसल पर चार बार संकट आया और इस सम्बन्ध में लोक सभा में भी अनेक बार चर्चायें हुई हैं, लेकिन उनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उत्तर प्रदेश में जो देश के आलू उत्पादन की 50 प्रतिशत पैदावार होती है उस पैदावार का 20 से 25 प्रतिशत केवल फर्रुखाबाद में होता है। 1981 में भी आलू के उत्पादन पर इसी तरह का संकट आया था। जिस पर यहां चर्चा हुई थी। मुझे मालूम नहीं माननीय मंत्री जी यहाँ थे या नहीं थे, लेकिन भारत सरकार के कुछ अधिकारियों ने उस समय कहा था कि उन्नत किस्म के बीज देने की जरूरत है, खाद देने की जरूरत है, आलू के लागत खर्च को कम करने की दृष्टि से वैज्ञानिकों को तकनीकी रिसर्च करने के लिए कहा गया था, व्यापारियों के लिए रेल-वैगन्ज उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, शीतगृहों की क्षमता बढ़ाने के लिए कहा गया था, नेफेड तथा अन्य संस्थाओं द्वारा ज्यादा तेजी से आलू खरीदने की बात कही गई थी, जिसका जिक्र आज भी इस वक्तव्य में किया गया है। आलू की बाइ प्राडक्ट्स की इण्डस्ट्रीज लगाने की बात कही गई थी, लेकिन अफसोस यह है — कही तो बहुत सी बातें थीं, लेकिन उनके बावजूद हुआ कुछ भी नहीं। हमारे देश में इस वर्ष खास तौर से आलू के मूल्य में भारी गिरावट आई है। किसान आज बहुत परेशान है। मैं स्पष्ट रूप से आज यह बात कहूंगा—आलू के सम्बन्ध में आज जो इतनी बड़ी कठिनाई आई है—इसका एकमात्र उत्तरदायित्व सरकार पर है।

सरकार हमेशा इसके प्रति लापरवाह रही है। बाजार मूल्य, लागत मूल्य और उपभोक्ता मूल्य, ये तीन मूल्य होते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं और अर्थशास्त्र के बारे में उनको काफी ज्ञान है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में कोई संकोच की

(श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री)

बात नहीं है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि बाजार मूल्य, लागत मूल्य, और उपभोक्ता मूल्य इन तीनों मूल्यों में बाजार में आलू के मामले में कोई सामंजस्य नहीं हैं। एग्रीकल्चर प्राइसेज कमीशन हमारा है, जिसके द्वारा मूल्य आप निर्धारित कराते हैं। इसकी जो मूल्य निर्धारण की प्रणाली है, वह अत्यन्त दूषित है। कीमतें निश्चित करते हुए चाहे वह आलू हो, चाहे कपास हो और चाहे गेहूं हो, कुछ खास बातों की जरूरत पड़ती है लेकिन मैं देखता हूं कि एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन उन बातों पर ध्यान नहीं देता है। समय, श्रम, मशीन, मैटीरियल, सूद की दर, लागत मूल्य, बाजार मूल्य, इन सब चीजों का समामंजस्य होना चाहिए लेकिन एग्रीकल्चर प्राइजेज कमीशन कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपने ढंग से पालिसी बना कर मूल्यों को निर्धारित करता है। हमें खेद है कि इसी तरह से गेहूं का मूल्य निर्धारित हुआ है और कपास का मूल्य निर्धारित हुआ। आज मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने नेफेड को कहा है कि वह 50 रु. क्वींटल के हिसाब से आलू खरीदे लेकिन मैं देखता हूं कि आज तक आलू का मूल्य सही ढंग से निर्धारित नहीं हुआ है। एक बार पहले भी 1981 में आपने नेफेड को आलू खरीदने के लिए कहा है और राजकीय सहकारी समितियों को भी आलू खरीदने के लिए आपने आदेश दिया था और यह कहा था कि 300 क्वींटल प्रतिदिन वे आलू खरीदें लेकिन तीन महीनों में दोनों संस्थाओं ने मिलकर केवल 1 हजार टन आलू खरीदा। आपने आदेश दिया है कि 50 रु० प्रति क्वींटल आलू खरीदा जाए लेकिन आलू 35 रुपये से 50 रु. प्रति क्वींटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। जब सरकार का आदेश 50 रुपये प्रति क्वींटल आलू खरीदने का है तो नेफेड क्यों 35 रुपये प्रति क्वींटल खरीदता है, क्यों वह 40 रुपये प्रति क्वींटल खरीदता है और क्यों वह 45 रुपये प्रति क्वींटल खरीदता है। यह हमारी समझ में नहीं आता हैं। इस कालिंग एटेंशन के द्वारा हम मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि कब तक इस मुल्क का किसान अपनी चीजों को इस अनिश्चितता के वातावरण में ला कर निकालता रहेगा। मैं समझता हूं कि इस सन्दर्भ में आपने कोई ध्यान नहीं दिया है।

मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। आलू कामू ल्य जून 1983 में कर्नाटक में 300 रुपये क्वींटल था और आलू का मूल्य उसी महीने में उत्तर प्रदेश में 170 रुपये क्वींटल था और वेस्ट बंगाल में 180 रुपये क्वींटल था, महाराष्ट्र में 280 रुपये क्वींटल था और नवम्बर 1983 में महाराष्ट्र में आलू का मूल्य 300 रुपये क्वींटल था, पंजाब में 200 रुपये क्वींटल था, बिहार में 180 रुपए क्वींटल था और पश्चिमी बंगाल में 280 रुपए क्वींटल था। ये दोनों भाव हमने पढ़े है और इन दोनों भावों को यदि देखा जाए, तो एक ही महीने में यदि महाराष्ट्र में आलू 280 रुपए क्वींटल है, तो पश्चिम बंगाल में 160 रुपए क्वींटल है। इतना फर्क होता है कर्नाटक के भाव में और उत्तर प्रदेश के भाव में और यह फर्क 125 रुपए से 150 रुपए प्रति क्वींटल होता है। आप कहते हैं कि हम यातायात की सुविधायें देते हैं। आपने अपने बयान में कहा है कि हमने रेल मत्रालय से बात की है और वेगनों की सुविधायें उपलब्ध कराई और दूसरी सुविधायें उपलब्ध कराई। मैं मान लेता हूं कि आपने सारी सुविधायें उपलब्ध कराई। फिर भी यू० पी० और कर्नाटक के भावों में एक क्वींटल के अन्दर 120 रुपये से 180 रुपए का अन्तर है। इतना ज्यादा अन्तर होने की तुक क्या है। मंत्री जी मेरे इस सवाल का जवाब दें कि आलू के मूल्य में एक

प्रान्त और दूसरे प्रान्त में 10-20 रुपए के अन्तर की बात तो समझ में आत है लेकिन यह जो 100, 125 रुपए का अन्तर है, यह क्यों है और इसको दूर करने का प्रयास क्या मंत्री जी करेंगे। आपने इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कभी सोचा है। इन दो, तीन और चार वर्षों में आपने इस बारे में क्या किया है, इस को बताने की कृपा मंत्री जी करें। आलू की फ़सल इस साल बहुत अच्छी हुई है और अर्थशास्त्र का यह नियम है कि जब डिमाँड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, तो दाम बढ़ते हैं और जब सप्लाई बढ़ती है और डिमांड कम होती है, तो मूल्य घटते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारा कृषि मंत्रालय हर साल उपज का मूल्यांकन करता हैं। आप हमेशा हाउस में हमको बताते हैं कि इस साल फसल अच्छी हुई है। इस साल इतने क्वींटल आलू होगा, इतने क्विटल गेहूं होगा। आपके अनुमान भी बहुत सही निकलते हैं। 1981 में घोषणा की गई थी कि 90 लाख टन आलू पैदा होगा और 96 लाख टन पैदावार हुई। इसी प्रकार 1982 में घोषणा की गई कि 100 लाख टन पैदावार होंगे और 105 लाख टन पैदावार हुई। इस तरह से आप का अनुमान करीब-करीब सही निकलता है। इतना अच्छा आपका संत्र है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार को मालूम हो जाता है कि इतना आलू होगा तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि देश में डिमांड क्या है। किस तरह से डिमांड और सप्लाई में समानता पैदा कीजिए, यह भी आपको सोचना चाहिए। जिस साल आप घोषणा करते हैं कि आलू की फसल बहुत अच्छी होगी उसी साल किसान को रो-रो कर अपना आलू बेचना होता है। अभी मैं पढ़ रहा था कि 18 हजार मीट्रिक टन आलू बंगाल में सड़ गया, उसको फेंक दिया गया। इस तरह से आप देखिए कि यह कितनी गम्भीर समस्या है इसके लिए मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं कि आप किसानों की बुरी दशा के लिए जिम्मेदार हैं। आपको डिमांड मालूम है, सप्लाई मालूम है, उसका रेट मालूम है, आपके पास सब संस्थायें हैं, फिर भी आलू की यह स्थिति है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर मेरा आरोप गलत है तो फिर यह स्थिति क्यों आई जबकि सरकार ने आलू की पैदावार का अनुमान लगाया हुआ था। इसके बाद फिर डिमांड और सप्लाई में संतुलन बनाने के लिए आपने कार्यवाही की।

इस सन्दर्भ में एक बात और बताना चाहता हूं। मंत्री जी ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि हमारे यहां दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा और अच्छा आलू पैदा होता है और स्वादिष्ट होता है। लेकिन इसकी खपत अन्य देशों के मुकाबले कम है। जर्मनी में एक आदमी 174 किलो ग्राम आलू खाता है, बेल्जियम में 146, डेनमार्क में 132 अमरीका में 84 और भारत में एक आदमी 10 किलोग्राम आलू खाता है। जरमनी, बैल्जियम, डेनमार्क, अमरीका हमारे यहां की तुलना में कम आलू की पैदावार करते हैं, विदेशों से मंगाते हैं। बैल्जियम से 4 गुना ज्यादा और जरमनी से 6 गुना ज्यादा उत्पादन हम करते हैं लेकिन खपत हमारे यहां कम है। इस खपत को बढ़ाया जाना चाहिए। पिछले 30 वर्षों में हमारे यहां आलू के उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी खपत को बढ़ाने के लिए ध्यान नहीं दिया गया है। आप अब इसके संबंध में क्या करने जा रहे हैं। एक बार इसके सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। उसमें बताया गया था कि जर्मनी में शराब, बीयर और दूसरी बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। हमारे यहां भी इस ओर ध्यान दिया जाएगा, यह कहा गया था। केन्द्र सरकार का तो मुझे नहीं मालूम लेकिन उत्तर

(श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री)

प्रदेश सरकार का एक स्टेटमेंट मेरे पास है। उसमें कहा गया था कि हम इस किस्म की चीजें बनायेंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार इन पर विचार कर रही है? क्या केन्द्रीय सरकार आलू की खपत बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देगी कि इस प्रकार की चीजों को फैक्टरियाँ बनायें, या केन्द्रीय सरकार उनको कुछ अंशदान देगी। लागत मूल्य बाजार मूल्य और उत्पादन मूल्य में सामंजस्य नहीं है। आज दिल्ली में आलू का थोक मूल्य 60 पैसे और 65 पैसे किलो का है जबकि नार्थ एवेन्यू में दो रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : What do you want Government to do in this regard Please come to the point. That is very important.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : वाराणसी में थोक मूल्य का कल का रेट 70 पैसे था जबकि फुटकर मूल्य डेढ़ रुपए किलो का था। 65 पैसे और दो रुपए में कितना अन्तर है, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। किसान को 65 पैसे मिलते हैं और व्यापारी को दो रुपए मिलते हैं। इसलिये, मैं जानना चाहूंगा कि इस बीच के अन्तर को हटाने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? गेहूं और गन्ने का मूल्य निर्धारण आप कर लेते हैं लेकिन आलू का मूल्य निर्धारित करने में क्या कठिनाई है ? मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस राष्ट्रीय फसल को अगर बचाना है तो आपको कम से कम 100 रुपए प्रति क्विंटल का भाव निश्चित कर देना चाहिए। इस कालिंग अटेंशन के तत्काल बाद अपने मंत्रालय से राय लेकर आप यह घोषणा करें कि आलू का सौ रुपए क्विंटल का भाव निर्धारित कर रहे हैं और नेफेड तथा दूसरी संस्थाओं को भी आलू खरीदने के लिए कह दिया गया है।

MR. DEPUTY SPEAKER : It has been stated in the statement Officers of NAFED have already visited the area and they have been directed to make purchases in Uttar Pradesh at a support price of Rs. 50 per quintal.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : पचास रुपए क्विंटल से तो किसान को लागत मूल्य भी नहीं मिलता है।..... (व्यवधान)

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : 150 रुपये के रेट के हिसाब से देना चाहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सारे देश का किसान आपको दुहाई देगा, अगर यह रेट कर दिया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then you say, support price is less.

SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI : That should be more ; I want Rs. 100 per quintal.

MR. DEPUTY SPEAKER : Please note that. You can put questions like these. Basing on the statement if you put your question that would be better. You are not satisfied with Rs. 50. You want it to be Rs. 100.

SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI : I want Rs. 100 per quintal.

आलू की फसल को सुनियोजित ढंग से चलाना है तो हमें इसके निर्यात वाले पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। भारतीय आलू की मांग विदेशों में बहुत ज्यादा है। आपने राज्य-मभा में कहा था कि इन्टरनेशनल मार्किट में

यहां के आलू की मांग अधिक है तथा वह मंहगा पड़ता है। यह भी कहा था कि नेशनल पोटाटो रिसर्च इन्स्टीट्यूट अच्छे किस्म का आलू पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सरकार द्वारा सुव्यवस्थित रूप से ध्यान न देने के कारण निर्यात में काफी परेशानी हो गई है। इस मामले में आप बहुत उदासीन हैं। शिमला के नेशनल पोटेटो रिसर्च इन्स्टीट्यूट के डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था निर्यात की स्थिति को देखते हुए जो हमारे मुल्क में है, विदेशों की आप शिकायत है कि भारत का आलू विदेशों में नियमित रूप से आवश्यक मात्रा में निर्यात नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में चाहते हुए भी इन देशों को दूसरे देशों से आलू 4,5 गुने दाम देकर मंगाना पड़ता है। नेशनल पोटेटो रिसर्च इन्स्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री वी. पी. नगाइच ने अपने एक इन्टरव्यू में कहा था कि हमारे यहाँ पोटेटो सम्बन्धी ऐसी कोई सुव्यवस्थित संस्था नहीं है जो इस दिशा में सुचारू रूप से 30 साल के आंकड़ों को देखते हुए कार्य कर सके। अगर सुचारू रूप से भारत का आलू विदेशों में भेजा जाय तो इसको 'सी' प्रायरिटी मिलेगी और हमारा पोटेटो क्रौप एरिया तिगुना लाभ प्राप्त कर सकेगा। मैं जानना चाहता हूं क्या यह रिपोर्ट सही है ? यदि हाँ, तो आप भारत से विदेशों को आलू निर्यात करने के बारे में क्या सोच रहे हैं ?

आलू का कोल्ड स्टोरेज से काफी सम्बन्ध है, आलू हमेशा वहीं रखा जाता है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज की स्थिति इस समय बहुत ही बुरी है जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जिस समय आलू का भाव ऊंचा होगा उस समय कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने की दर नीची होगी, और जब आलू का रेट नीचा होगा तो कोल्ड स्टोरेज की दर ऊंची हो जाएगी। कोल्ड स्टोरेज के मालिक किसानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं रखते हैं। जब आलू का भाव ऊंचा होगा तो अपने पैसे से खरीदवा कर अपने यहां कोल्ड स्टोरेज में रखवा लेंगे। बिजली वालों से भी उनकी बातचीत हो जाती है। लेकिन जब आलू की पैदावार ज्यादा होगी तो कोल्ड स्टोरेज में रखने के समय कहा जाता है कि जगह नहीं है।

एक बार आपके आलू वैज्ञानिक ने घोषणा की थी कि हम 5,000 रुपए का एक छोटा सा यंत्र देंगे जो किसानों के घर पर पहुंच जाएगा जिससें चिप सुखाने में, पापड़ सुखाने में, उनको सहायता मिलेगी। इससे किसनों का हौसला ऊंचा हुआ था। लेकिन यह योजना ऐसे ही रह गई। मैं सुझाव दूंगा कि आप कोल्ड स्टोरेज की स्थिति पर जरूर नियंत्रण करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्ड स्टोरेज के लिए एक फौरमूला तैयार किया था, मूल्य निश्चित किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि वह फौरमूला केवल कागज पर ही रह गया। कोल्ड स्टोरेज के मालिक आलू के ऊपर अपना सारा कारोबार निश्चित करके किसानों को बुरी तरह से शोषण करते हैं और किसान अपनी व्यथा नहीं कह सकता। मैं चाहूंगा आलू के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के मंत्रियों को बुला कर के एक गोष्ठी करे आप उनको अंशदान दें, आधा - आधा बेसिस पर, या जैसे आप उचित समझें, और हर जिले में बहुत बड़े कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करवायें जिससे किसान अपना आलू वहां रख सके।

हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक 36 करोड़ 5 लाख रुपए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए दे रहा था। और इसकी बड़ी चर्चा भी थी, हम

(श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री)

लोग भी खुश थे कि इस काम के लिए वर्ल्ड बैंक सहायता दे रहा है जिससे इस केश क्रौप को लाभ होगा। लेकिन वह मामला भी अधर में पड़ा रह गया।

आपने कहा है कि रेल मंत्रालय से सम्बन्ध स्थापित करते हैं वैगनों के लिए। इस ओर आपने ध्यान दिया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यह केवल कागज पर ही है। इस बारे में मैं आपको मिशाल देता हूं। फर्रुखाबाद में 1982 में ज्यादा आलू पैदा हुआ था, लेकिन उस साल 1981 की बनिस्बत कम रेल वैगन वहां पहुंचे। उस समय केवल 1900 वैगन्स पहुंचे थे। और जब आलू की फसल कम हुई थी उस वक्त 2,400 वैगन पहुंचे थे। यह क्या तमाशा है ? आप रेल वैगनों के बारे में रेल मंत्री से बात कर लें। अगर यह आप ठीक कर लेते हैं, समय से पहुंचा देते हैं, ट्रांस्पोर्ट की सुविधा प्रदान कर देते हैं तो हर प्रान्त के आलू के भाव में सामंजस्य रहेगा और आलू एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा।

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Shastri you have done very good homework for a discussion under rule 193—not for Calling Attention. I have allowed you 25 minutes.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मंत्री महोदय, मेरे प्रश्नों का उत्तर दें और साथ ही इस दिशा में जरूर सचेत रहें कि आलू की पैदावार की रक्षा ठीक ढंग से की जाये। आलू ही नहीं, इसमें तमाम सब्जियां ली जायें। आज देश में सब्जी की हालत बहुत खराब है। वाजार में टमाटर और मटर 8 रुपए किलो विक रहे है जबकि किसान को 2 रुपए किलो मिलते हैं। हर अवस्था में किसान सफर कर रहा है।

सब्जियों के मामले में आप कितने जागरूक हैं, बीज देते हैं, नियन्त्रण करते हैं, रिसर्च करवा रहे हैं, लेकिन आपको मूल्य मामले में भी नियन्त्रण करना चाहिए। आलू के मूल्य 100 रुपए क्विंटल निर्धारित करके आलू के किसान की आप रक्षा करें।

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : माननीय सदस्य ने खुद माना है कि आलू की पैदावार काफी बढ़ी है। मेरी मिनिस्ट्री का जिम्मा तो पैदावार बढ़ाने का है। देश में आलू की पैदावार बढ़ी है, इससे साबित होता है कि बहुत सी सुविधायें सरकार की तरफ से आलू उपजाने के लिए किसानों को दी जाती हैं। बीज अच्छा पैदा किया गया है, जिसमें बीमारियां कम रहें। जिस तरह से आलू की पैदावार बढ़ी है, इससे जाहिर होता है कि किसान के लिए आलू लाभदायक है। उसको अच्छी कीमतें मिलती रही हैं। अगर किसान को कीमत अच्छी नहीं मिलती तो उसकी पैदावार घटती।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : किसान तो मजबूर है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मजबूरी की बात नहीं है। आपने खुद कहा कि पिछले सालों में 110 और 120 रुपये तक आलू की कीमतें मिलीं, बंगाल यू० पी० और बिहार में।

पिछले साल भी एक बार कठिनाई आई थी, आलू की कीमतें गिरने लगी थीं। यू० पी० सरकार से बात कर के हमने जो उपाय किये, उनसे कीमतें फिर बढ़नी शुरू हो गई और सरकार को खरीदना नहीं पड़ा। यू० पी० में चीफ मिनिस्टर उस वक्त श्री वी० पी० सिंह थे। उन्होंने कहा था कि जो उपाय ज्यादा वैगन मुहैय्या करने के लिए किए जा रहे हैं, हम आलू दूसरे प्रान्तों को भेजने की बात कर रहे हैं, उससे

जरूरत नहीं पड़ेगी कि सरकार की एजेंसियां आलू खरीदें।

उससे पहले भी एक बार कीमतें गिरी थीं जिसका आपने जिक्र किया। तब पंजाब, बिहार, यू० पी० में रोजाना आलू खरीदने के लिए नाफेड को, सरकारी एजेन्सी को कहा था और उससे भी कीमतें बढ़ गई थीं। किसान को नुकसान नहीं होने दिया गया। आलू के लिए ही नहीं, दूसरी चीजों के लिए भी, अगर जरूरत पड़ी तो किसान को नुक्सान से बचाने के लिए सरकार कदम उठाती है। जैसे प्याज के लिए पहले किया था और अब प्याज के लिये महाराष्ट्र और गुजरात में कर रहे हैं।

यह सही है कि आलू की कीमतें इस तरीके से मुकर्रर करके खरीद की गारन्टी नहीं की जाती, जैसे कि अनाज की की जाती है। एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन भी कीमतें मुकर्रर करने के लिये कोई सिफारिस नहीं करती। आलू और दूसरी सब्जियाँ खरीद कर उन्हें रखने और इस्तेमाल का बन्दोवस्त सरकार नहीं कर पाती, इसलिए यह जिम्मेदारी भारत सरकार नहीं ले सकती।

एक तरफ आपने कहा कि आलू की खपत हिन्दुस्तान में साल भर में फी आदमी 10 किलोग्राम है जबकि दूसरे मुल्कों में एक-एक आदमी 200 किलोग्राम खा जाता है। यह गरीबों के लिए सस्ता भोजन है। हिन्दुस्तान में आलू की खपत इतनी कम है, हालांकि यहां पर गरीब आदमियों को पूरे कार्बो-हाइड्रेट और प्रोटीन नहीं मिल पाते हैं। इसकी कीमत कहां तक बढ़ाई जा सकती है? माननीय सदस्य कनज्यूमर की तरफ भी देखें। यह सस्ती सब्जी है। गरीब आदमी भी इससे रोटी खा सकता है। अगर इसकी कीमत मुनासिब रहे, तो आम उपभोक्ताओं को फायदा होता है। दोनों तरफ निगाह रख कर चलना पड़ेगा।

किसान को आलू की कीमत ऐसी मिलनी चाहिये कि उसे उत्पादन में नुक्सान न हो। सरकार इस बात का ध्यान रखती रही है और अपनी जिम्मेदारी निभाती रही है। जैसा कि मेरे साथी, श्री मकवाना, ने अपने वक्तव्य में कहा है, ज्यों ही हमें यह खबर मिली, हमने नाफेड और यू० पी० गवर्नमेंट को खरीद शुरू करने के लिए कहा। मैंने पहले बताया है कि भारत सरकार यह जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर अपने सिर पर नहीं ले सकती कि अगर सब्जी या फल की कीमतें गिरें, तो वह खरीदें और यह नुक्सान पूरा करे। स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हमें उम्मीद है कि हमने जो उपाय किए हैं, उनसे आलू की कीमतें बढ़ेंगी।

यू० पी० में 27 मार्च तक तो कीमतें ठीक मिल रही थीं और किसानों को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उसके बाद अचानक कीमतें गिरनी शुरू हो गयी। उसकी कई वजहें हो सकती हैं, जिनमें से एक यह है कि किसान समझ रहे थे कि पिछले साल की तरह कीमतें ज्यादा मिलेंगी और इसलिए जहां तक उनसे हो सका, उन्होंने मण्डी में आलू कम भेजा, उसको रोका। व्यापारियों ने भी शायद खरीद कम की, ताकि जब किसान तंग आ कर मंडी में आलू लायेंगे, तो हमको कम कीमत पर मिल जाएगा अचानक गर्मी का मौसम शुरू हो गया। जब किसानों ने आलू बेचने की कोशिश की तो व्यापारियों ने उसका नाजायज फायदा उठाया। ऐसे मौके पर कोल्ड स्टोर वाले भी नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जब इस तरह भगदड़

(राव बीरेन्द्र सिंह)

मचती है, तो हर एक आलू के लिए कोल्ड स्टोर लेने की कोशिश करता है। अगर किसान आलू न बेचे, तो वह उसके घर में बर्बाद हो जाता है। ब्यापारी समझता है कि अगर कीमत और कम हो जाए, तो मैं खरीदूं। कोल्ड स्टोर वाले ज्यादा चार्ज करना शुरू कर देते हैं। यू० पी० में कोल्ड स्टोर वालों ने 19 रुपए पर क्विंटल से अधिक लेने शुरू कर दिया। इस बारे में यू० पी० गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए और कोल्ड स्टोर वालों को कहा कि वे मुनासिब कीमत चार्ज करें और व्यापारियों की निस्वत किसानों को प्रेफरेंस दें।

कोल्ड स्टोरों का एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकारों के नीचे है, भारत सरकार इसका बन्दोबस्त नहीं कर सकती। लेकिन यू० पी० गवर्नमेंट इस मामले में सचेत है। हम यू० पी० गवर्नमेंट को जितनी सहायता दे सकते थे, वह हमने दी है और मंडियों में आलू की खरीद शुरू हो गई है नेफेड और यू० पी० सरकार की तरफ से। हम उम्मीद करते है कि आलू की कीमत ठीक हो जाएगी।

इसमें कोई शक नहीं कि कोल्ड स्टोर ज्यादा होने चाहिए। आलू जैसे चीजें और वगैर कोल्ड स्टोर के नहीं रखी जा सकतीं। कोआपरेटिव्ज के कोल्ड स्टोर मेरी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है और रूरल एरियाज के बाकी कोल्ड स्टोर रूरल डैवैलपमेंट मिनिस्ट्री के नीचे है। यू० पी० में कोआपरेटिव्ज के कोल्ड स्टोर काफी हैं। वहां पर कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी 1.16 लाख टन है। इस वारे में सारी बातों को यू० पी० गवर्नमेंट देख रही है।

श्री राजराथ सोनकर शास्त्री : आलू का उत्पादन कितना है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह अन्दाजा लगाया गया है कि इस साल की फसल यू० पी० में 52 लाख टन की है। यू० पी० में करीब 50 प्रतिशत आलू का उत्पादन होता है। देश का 30 फीसदी के करीब आलू यू० पी०, बिहार और बंगाल में पैदा होता है और 20 फसदी बाकी हि दुस्तान में पैदा होता है। लेकिन यह कठिनाई यू० पी० में आम नहीं है। कीमतें ज्यादा गिरी हैं इन चार डिस्ट्रिक्ट्स में : फर्रुखाबाद मैनपुरी, एटा और इटावा।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : बदायूं में भी घटी है।

राव बीरेन्द्र सिंह : बदायूं में भी घटी होगी। लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूं। जयपाल सिंह कश्यप जी को भी बोलने का मौका मिलेगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : राव साहब, बिहार में भी वही हालत है।

राव बीरेन्द्र सिंह : जी हां, बिहार के अन्दर भी हो सकता है। लेकिन अभी हमारे पास कोई खबर नहीं है।

यू० पी० में भी अभी जिन दिनों में कुछ जिलों में कीमतें 40 से नीचे तक चली गई वहां पर नजदीक के जिलों में कीमत 70-80 तक थी, जैसे कानपुर में। तो जिले जिले में यू० पी० में फर्क है।

आप कहते हैं कि महाराष्ट्र में और कर्नाटक में आलू की कीमतें इतनी ज्यादा होती है तो क्यों नहीं ऐसा बन्दोवस्त हो सकता कि आलू यहां से लेकर वहां पहुंचा दिया जाए ? वह तो

आप दूसरे प्रान्त और रीजन की बात कर रहे हैं जहां प्राइसे डिफरेंशियल इतना ज्यादा है, आप दिल्ली की बात कीजिए। यहाँ सब्जी मंडी के अन्दर आठ आने किलो एक किसान सब्जी बेच जाता है और आप अपने एम. पीज. के रेजीडेंस के नजदीक या खान मार्केट में कहीं चले जाइये तो वहां पांच गुना या छः गुना ज्यादा कीमत मिलेगी उसी आठ आने किलो वाली सब्जी की। तो इसके लिए सरकार कन्ज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर्स खोलने के लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। आप बना लीजिए अपनी कोआपरेटिव, सब्जी मंडी से ला कर सस्ती मुहैया करिए सारे एम. पीज. को, आपको इतनी ज्यादा कीमत नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन सरकार इस एक पेरिशेबल चीज के लिए कितनी दूकानें खुलवा सकती है, क्या-क्या कर सकती है ? उसके लिए सिविल सप्लाइज मिनिस्ट्री की तरफ से जितना हो सकता है वह कर रहे हैं। हम कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर खोलने के लिए मदद देने के लिए तैयार हैं।

आपने एक बात की, बिलकुल सही बात है कि निर्यात अगर ज्यादा हो तो इससे कीमत किसान को अच्छी मिलेगी या देश के अन्दर खपत बढ़े। देश के अन्दर खपत बढ़ेगी तब, जब लोगों का शौक बढ़े और लोगों के पास पैसे हों, शक्ति हो आलू ज्यादा खाने की, तब खपत बढ़ेगी। निर्यात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ओपेन जनरल लाइसेंस है, आप चाहे जितना आलू चाहे जिस मुल्क को भेज सकते हैं। कामर्स मिनिस्ट्री से इजाजत है पूरे तरीके से। क्यों नहीं एक्सपोर्ट ज्यादा हो पा रहा है? वह इसलिए कि इंटरनेशनल प्राइजेज आलू की इतनी कम है कि यहां से भेजने वाले को उसमें फायदा नहीं है। दूसरे मुल्क यहां का आलू खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि आलू की पैदावार और मुल्कों के अंदर हिंदुस्तान की निस्वत फी यूनिट ज्यादा है और कास्ट आफ प्रोडक्शन भी कम है। मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन है। यहां छोटे-छोटे किसान पैदा करते हैं। तो यहां की कास्ट ज्यादा है और इंटरनेशनल प्राइजेज कम है। वहां की कास्ट कम है। इस लिए निर्यात ज्यादा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कामर्स मिनिस्ट्री काफी कोशिश कर रही है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : एक स्टेटमेंट दिया है आपके डायरेक्टर ने···

राव बीरेन्द्र सिंह : अब मैं आ रहा हूं सारी बातों के ऊपर।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उन्होंने यह कहा है कि बाहर ज्यादा कीमत···

RAO BIRENDRA SINGH : You cannot ask for an opinion from me. Sir, he cannot force me to give an opinion ; nor can he discuss the opinion of somebody else in the House. He has asked for some information and I am giving him.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप मिसलीड कर रहे है···(**व्यवधान**)···

राव बीरेन्द्र सिंह : जी नहीं।···

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जो हम आपसे पूछ रहे हैं···(**व्यवधान**)·····

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं वही बता रहा हूं। आप ओपिनियन क्या है उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते। कायदे की बात बता रहा हूं। जो आप इन्फोर्मेशन चाहते हैं वह सुनिए। बाकी बातों में पड़ कर क्या करियेगा ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप इतने तैश में क्यों आ रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इसलिए कि आप तैश दिला रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप इतने तैश में क्यों हैं ? मैंने तो यह ध्यान दिलाया कि आपके डायरेक्टर ने यह कहा है···

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has expressed his own opinion. Shastriji, You must wait till he completes his reply. Then You can ask for any clarification; not in the middle.

RAO BIRENDRA SINGH : The hon. Member does not seem to be interested in getting the information. Therefore, I have to stop it and sit down. I was trying to explain.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have made all your points for 25 minutes, Shastriji.

RAO BIRENDRA SINGH : Do not try to interrupt like this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shastriji, I think you have not taken potatoes this morning. Do not interrupt the reply, because the cogency will go.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपका मैं आदर करता हूं, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं सारी चीजें आराम से समझाना चाह रहा था। लेकिन अगर माननीय सदस्य समझना नहीं चाहते हैं तो मैं बिलकुल मजबूर नहीं करना चाहता। मैं तो बैठने के लिए तैयार हूं। इनको यह हक नहीं है कि बीच में उठ कर टोकें तो अपनी गलती को नहीं महसूस कर रहे हैं। किस लिए बार-बार उठते हैं? मैंने उन को कभी नहीं टोका, जब वह बोल रहे थे।··· ...(व्यवधान)...बीच में जिस तरह से टोकने की कोशिश की वह बिलकुल गलत किया।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं यह अर्ज कर रहा था कि आपकी एक इंफोर्मेशन और गलत है कि वर्ल्ड बैंक से जो हमारा कोआपरेटिव सेक्टर में कोल्ड स्टोरेज लगाने का प्रोजेक्ट है वह नहीं चल रहा है। आपकी यह इत्तला गलत है। हम कोल्ड स्टोरेज लगा रहे हैं यू. पी. में, बिहार में बहुत से कोल्ड स्टोरेज लगा रहे हैं। वह स्कीम चल रही है और उससे कोआपरेटिव कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ेगी।

आपने प्रोसेसिंग की बात कही है। आलू की ज्यादा प्रोसेसिंग होनी चाहिए—इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि तभी किसान को ज्यादा कीमत मिलेगी। इसके लिए हमारी पालिसी है कि ज्यादा से ज्यादा वेजेटेबल और फ्रूट्स की प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जायें। कोआपरेटिव्व की तहत लगें और प्राइवेट इण्डस्ट्रीज भी लगायें। हम उनको पूरी-पूरी सहायता देने के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए कर्जा भी मिलता है। कोआपरेटिव को एन. सी. डी. सी. से हेल्प देने के लिए तैयार हैं प्रोजेक्ट तैयार कराने में भी सहायता करने को तैयार हैं। अभी हमने नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड बनाने का भी फैसला किया है। पिछले दिनों उसका ऐक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड बनाने का मकसद भी यही है कि प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता मिले ताकि इण्डस्ट्रीज बढ़ें, पैदावार भी बढ़े और रिसर्च भी हो। स्टेट गवर्नमेंटस या कोई दूसरी एजेन्सीज इसको करना चाहें तो उनको भारत सरकार की तरफ से पूरी सहायता मिलेगी, बोर्ड की तरफ से सहायता मिलेगी। यह सारा काम इसीलिए किया गया है कि जो तकलीफें आप बता रहे हैं किसानों की, उनको दूर कराया जा सके।

इस बात को हम मानते हैं सब्जियों और फलों का जो उत्पादन देश में होता है उनसे भी किसान कमाता है और यह भी जरूरी है उनको इसकी मुनासिब कीमतें मिलें। सरकार इस पालिसी को मानती है। जैसाकि आपने सुझाव दिया है कि किसान को पैदावार में नुकसान नहीं होना चाहिए, उसी के मुताबिक, जैसा मैंने कहा, वक्तप-फवक्तन जब भी जरूरत पड़ती है, हम मुनासिब उपाय करते है। अभी जब मालूम हुआ कि आलू की कीमतें गिर रही हैं तो उनको सम्हालने के लिए हम मदद कर रहे हैं और आगे भी जैसी जरूरत होगी सरकार कदम उठाने के लिए बिलकुल तैयार हैं। जहां तक रेलवे वैगन्स की बात है, रेलवे वैगन्स की कमी इस वक्त नहीं है। इसलिए आपकी यह इत्तला भी गलत है। यू. पी. सरकार ने खुद लिखा और माना है कि रेलवे वैगन्स काफी मिल रहे हैं रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से। हम उम्मीद करते हैं कि आगे कीमतें आलू की बढ़ सकेंगी। नाफेड और स्टेट एजेंसीज को हमने इस बात की इजाजत दी है कि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर 11 रुपये क्वींटल तक का घाटा खुद आधा आधा बर्दाश्त करके 20 हजार टन आलू फौरन खरीद लें और उसके बाद आगे के लिए निगाह रहे, अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी खरीद लेंगे। लेकिन इस वक्त की आलू की खरीद से मैं समझता हूं गरीब किसानों को फायदा नहीं पहुंच सकेगा, खास तौर से उन गरीब किसानों को जोकि अपना आलू खोदकर पहले ही बेच चुके हैं क्योंकि वे दो-तीन महीने तक आलू को अपने पास नहीं रख सकते हैं। अब बड़े किसानों के पास आलू रह गया होगा या जो व्यापारी है, जिन्होंने छोटे किसानों से सस्ते में आलू खरीद लिया था, वही लोग सरकारी एजेंसीज़ को आलू बेचकर प्राफिट कमा सकते हैं। फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि अगर किन्हीं छोटे किसानों के पास आलू रह गया हो तो उनको नुकसान हो और इसी लिए सरकार मुनासिब कीमत कायम करने के लिए कोशिश कर रही है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार 'अमर उजाला' की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसमें लिखा है—आलू इस वर्ष खेतों में सड़ेगा : किसानों की बर्बादी के लक्षण। इसी प्रकार 4 अप्रैल को लिखा था—"अब आलू उल्टा किसान को खा रहा है।" बरेली से प्रकाशित समाचार अमर उजाला में लिखा था—"ये सरकारी शीतगृह आलू सड़ा रहे हैं।" माननीय सदस्य सोनकर जी ने सभी बातें उठा दी हैं, मैं बहुत ही थोड़े शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार ने आलू के बारे में कुछ गलत नजरिए से देखा है और आपकी पकड़ भी उस पर स्पष्ट नहीं है। क्योंकि अभी तक आलू खेतों में पड़ा हुआ है, उठा नहीं पा रहे हैं, बल्कि स्त्रोत भी नहीं गया है। किसान को उसका मूल्य इतना नहीं मिल पा रहा है कि उसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा, लेबर का खर्चा भी बर्दाश्त कर सके। बदायूं और बरेली जिले के देहात की स्थिति की यह है कि आलू 30 रु० क्विंटल से भी कम 15-20 रुपए क्विंटल तक बिका है। जिसकी वजह से उसको लेबर, खुदाई, कोल्ड स्टोरेज तक ले जाना और बाजार तक ले जाना भी मंहगा पड़ रहा है। इस समय इन्सान के खाने के लिए जितनी चीजें हैं. रोटी के साथ-साथ खाने की, चाहे दालें हों या सब्जी, इतना मूल्य बढ़ गया है कि आलू ही गरीब का भोजन रह गया है। आलू सस्ता बिके, हमेशा एक ही मूल्य पर मिलता रहे तो भी कोई बात नहीं है। जहां दो, तीन महीने गुजरते हैं आलू के मूल्य

(श्री जयपाल सिंह कश्यप)

आसमान की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अभी भी नार्थ एवेन्यू में आलू दो-ढाई रु० किलो बिक रहा है। वहीं देहातों में 15-20 पैसे किलो बिक रहा है। आज भी इतना अन्तर है। किसानों के पास से आलू चला गया, लेकिन कुछ समय बाद तीन-साढ़े तीन रुपए किलो हो जाएगा। यह बीच में जो फर्क होता है, इससे तो उपभोक्ता का भी शोषण होता है। व्यापारी का मुनाफा बढ़े, लेकिन इससे उपभोक्ता का भी शोषण बढ़ जाता है। आपको इस ढंग से भी सोचना है कि आलू का मूल्य इसलिए घटा रहे हैं कि उत्पादन बढ़ गया है, तो वास्तव में बढ़े हुए उत्पादन का आलू तो अभी तक निकाला भी नहीं गया है, वह तो अभी भी खेतों में सड़ रहा है। जितना उसका उपयोग बढ़ता जाएगा, उतना ही आलू का मूल्य कम से कम संतुलित होना चाहिए था, लेकिन आलू बाजार में आने से पहले भाव बढ़ता चला जा रहा है। सरकार गलत नजरिए से सोच रही है कि आलू की पैदावार है, इसलिए आलू का मूल्य घट रहा है, जबकि यह वास्तविकता नहीं है। सरकार को इस पर बड़ी ही गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। आपने पहले कहा कि नाफेड 50 रुपए क्विंटल आलू खरीदे, ऐसी हिदायत दी गयी है। पहले वायदा किया गया था कि 55 रुपए क्विंटल खरीदेगा। वही तीन साल पहले का भाव दिया जा रहा है, जब कि खाद मूल्य, सिंचाई और बिजली का मूल्य, बीज और मजदूरी के दाम कितने बढ़ गए हैं। लेकिन इसमें अभी तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है। किसानों को उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है।

जहाँ तक फैक्ट्रियों का सवाल हैं, इसके लिये आपको विशेष ध्यान देकर तादाद को बढ़ाना चाहिए। जैसी कि जानकारी मिली है सरकार ने वदायूं में अनुमति दी है, आलू की चीपस और दूसरी चीजें बनाने के लिए कारखाने का लाइसेंस दिया है। इसमें जल्दी होनी चाहिए, उसके निर्माण में जल्दी होनी चाहिए। बदायूं, बरेली, उन्नाव, मैनपुरी, फर्रुखाबाद जहां आलू की पैदावार बहुत अधिक होती है वहां इस प्रकार की फैक्टरियां कायम की जानी चाहिए ताकि आलू के चिप्स, आलू का पाउडर तथा दूसरी चीजें बनायी जा सकें। इस तरह से किसानों को अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज में कम से कम समय के लिए रखना पड़ेगा।

कोल्ड स्टोरेज की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है—उनका उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना है। बाजार में आलू की फसल आने के पहले ही कोल्ड स्टोरेज के मालिक व्यापारियों के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम इतने हजार क्विंटल आलू तुम्हारे लिए खरीदेंगे, जिस के लिए इतनी जगह रिजर्व कर रहे हैं। किसान जब आलू लेकर आता है तो कोल्ड स्टोरेज वालों से उनको जगह नहीं मिलती है और अगर किसी को जगह मिल भी गयी तो कोल्ड स्टोरेज वाले उससे कई गुना ज्यादा किराया वसूल करते हैं। कहीं कहीं तो बाध्य होकर किसान को 25 से 30 रुपए क्विंटल किराया चोरी से उन को देना पड़ता है। फर्रुखाबाद और कई अन्य जगहों पर ऐसा हो रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कोल्ड स्टोरेज के भाड़े के लिए जो निर्देश या नियन्त्रण सरकार ने किया है, उससे अधिक किराया किसान से न लिया जाय, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

अब जहाँ तक कोल्ड स्टोरेज की क्षमता का प्रश्न है—वह जरूरत के मुकाबले बहुत कम है। मेरा अनुरोध है कि कोल्ड स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाया जाय और इस समय जो आलू

मण्डियों में आ रहा है इस तरह की व्यवस्था की जाय कि कोल्ड स्टोरेज अपने क्षमता का 15 से 20 परसेन्ट तक अधिक माल अपने स्टोरेज में खपायें जिससे किसानों को लाभ हो। एक निवेदन यह है कि कुछ कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं जो इन्टरनेशनल बैंकों और राज्य सरकार की सहायता से बन रहे हैं। चन्दौसी और मेरे क्षेत्र आँवला में भी ऐसे कोल्ड स्टोरेज बने हैं और उन को 1984 में चालू हो जाना चाहिए था। उनकी बिल्डिंग बन गयी है, लेकिन पता नहीं वे अभी तक क्यों चालू नहीं हुए हैं। यदि वे चालू हो जाते तो उस क्षेत्र का आलू उनमें आसानी से खप सकता था और उससे किसानों को अच्छा मूल्य पाने का विश्वास हो सकता था। यदि सम्भव हो तो उनको चालू कराने का प्रयास करें ताकि आंवला और चंदौसी क्षेत्र के किसान उनसे लाभान्वित हो सकें।

एक जरूरी बात यह है कि कोल्ड स्टोरेज में किसानों का आलू पहले लिया जाय, व्यापारियों का बाद में भरा जाय। भंडारन में वरीयता किसानों को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार को इस तरह का प्रयास करना चाहिए जिससे कोल्ड स्टोरेज किसानों के आलू को वरीयता दे। मंत्री जी इस बात पर भी ध्यान दें कि आलू एक ऐसी उपज है जिस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके भण्डारन और मार्केटिंग में बहुत अन्तर है, क्योंकि इह को ज्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता है, जिस के कारण इस के मूल्य में फल्क्चुएशन होता रहता है। इस लिए मेरा सुझाव है कि आप एक अलग से विभाग बनायें जो तत्परता से आलू के काम को देखे, उसके मार्केटिंग, उस की खरीद और भंडारन को देखे। आप ने नाफेड द्वारा खरीद के लिए 55 रुपए का ऐलान किया था, पिछले तीन सालों में उत्पादन लागत बढ़ी है, इस लिए आलू के मूल्य को थोड़ा और बढ़ा कर खरीदने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। आलू से सम्बन्धित अन्य धन्धे लगाए जायें तथा कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने तथा कुछ अधिक मात्रा में रखने की व्यवस्था की जाय यदि सरकार ऐसा प्रयास करे, तब किसानों की कुछ सेवा हो सकेगी।

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं मैं उन का जिक्र पहले भी कर चुका हूं। इस तरह की हिदायात जारी हो चुकी हैं और यू० पी० सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने में किसानों को प्राथमिकता मिले। लेकिन इस बात को कहाँ तक लागू किया जा सकता है—यह कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि व्यापारियों द्वारा किसान के नाम से कोल्ड स्टोरेज में आलू लाया जाय तो कौन उस की जाँच करेगा कि यह व्यापारी का आलू है या किसान का आलू है। बहरहाल कोशिश यही हो रही है जैसा आनरेबिल मेम्बर चाहते हैं। आलू की समस्या असल में दूर तब होगी, जब देश के अन्दर कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी काफी बन जाएगी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोआपरेटिव सेक्टर में जितने भी कोल्ड स्टोरेज किसान लगाने चाहें या दूसरे लोग लगाना चाहें, उस के लिए हम पूरी, पूरी सहायता देंगे। आप कोशिश कीजिए कि जिन जिलों में आलू ज्यादा पैदा होता है, वहाँ लोग कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर अपने कोल्ड स्टोरेज बनायें।

इसके अलावा दूसरी स्कीमें भी हैं। रूरल मिनिस्ट्री की तरफ से रूरल गोडाउन्स की भी स्कीम है। उसके अन्दर 50 फीसदी तक सब्सीडी भी मिलती है। 50 फसीदी लोगों को अपने पास से लगाना होता है और 50 फसीदी सब्सीडी

(राव बीरेन्द्र सिंह)

सरकार की तरफ से दी जाती है, जिस में से आधा भारत सरकार देती है और आधा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। उस स्कीम का पूरा फायदा किसान उठायें, इस के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। हम तो बराबर लोगों को बताते रहते हैं कि ऐसी स्कीमें हैं और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ सजग रहना चाहिए।

आलू की कीमत की बात आनरेबिल मेम्बर ने कही। हमारे अन्दाजे के मुताबिक, जो मिनिस्ट्री ने अन्दाजा लगाया है, मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता, हो सकता है कि आप इस बात से सहमत न हों, 41 रुपए क्विंटल आलू की कास्ट आफ प्रोडक्शन है यू० पी० के इन इलाकों के अन्दर और 50 रुपए इसलिए तय किया गया है कि किसान को नुकसान न होने पाए। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि यह रेम्यूनेरेटिव प्राइस है और मैं यह भी नहीं मान रहा हूं कि हम आलू की सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं या किसानों को पूरा मुनाफा देने की बात है। यह तो जो कीमत गिरी है, तो सरकार ने अपनी पालिसी के मुताबिक कि किसान को नुकसान न होने पाए पैदावार के अन्दर, हम ने मार्केट के अन्दर इन्टरवेन्शन का यह तरीका निकाला है और इसमें हम कोई गारन्टी नहीं कर रहे हैं और ऐसी पालिसी हम अपनाने में, लागू करने में असमर्थ हैं कि जो भी सब्जी पैदा हो या फल पैदा हो, उसको अनाज की तरह भारत सरकार एक मुकर्रर कीमत पर खरीदना शुरू कर दे और उस का इस्तेमाल और उस का निर्यात शुरू कर दे। ऐसा करना नामुमकिन नजर आता है। यह जो सपोर्ट प्राइस 50 रुपये की है, इस के ऊपर अगर रेट रखा जाता है, तो वह इस बात पर निर्भर है कि यू० पी० गवर्नमेंट भी इस बात के लिए तैयार हो कि जितना नुक्सान किसान को हो, उसका आधा नुकसान वह बर्दाश्त करेगी और करने के योग्य है भी, और भारत सरकार और यू० पी० गवर्नमेंट दोनों उस नुकसान को उठाने के लिए तैयार हों और दोनों की सलाह से कीमत मुकर्रर हो। यह एक तरीका होता है और उस तरीके को हम ने अपनाया है। मैं आप से इस मामले में सहमत हूं कि किसान को हो सके, तो इससे भी ज्यादा कीमत मिलनी चाहिए लेकिन यह कठिनाई है, जो मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। यह मुमकिन नहीं है कि अपनी मर्जी होते हुए भी किसान को ज्यादा कीमत दिला सकें क्योंकि इससे एक प्रीसीडेंट भी कायम हो जाएगा। आलू ही खाली चीज नहीं है बल्कि और दूसरी चीजें हैं, दूसरी सब्जियां हैं, फल भी हैं और प्याज का भी मौसम अभी चल रहा है और उन के लिए कितना कुछ हम दे सकते हैं सारे भारत-वर्ष के लिये सेन्ट्रल लेविल पर कीमत मुकर्रर करना मुश्किल है और ऐसा बन्दोबस्त हम नहीं कर सकते। जहाँ कहीं भी तकलीफ होती है, वहाँ हम सहायता कर रहे हैं। यह बात स्पष्ट है और इसमें हम कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं।

फिर आपने उसी बात को दोहराया है, जो कि श्री सोनकर शास्त्री जी ने कही थी कि आलू की जो इतनी पैदावार हुई है, उस का इस्तेमाल देश के अन्दर हो। ऐसे कारखाने लगें, ऐसा हम भी चाहते हैं। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी चाहता है, फूड डिपार्टमेंट भी चाहता है और इसके लिये कोशिश कर रहे हैं। आलू की पैदावार बहुत बढ़ रही है और अगर इसका निर्यात नहीं हो सकता तो इसका इस्तेमाल इसी मुल्क में हो और इससे ऐसी चीजें बनाई जाएं जो दूसरे मुल्कों में आसानी से भेजी जा सकें।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : समय की विडम्बना है कि लोक सभा का अध्यक्ष किसान उपाध्यक्ष किसान, और कृषि मंत्री किसान। किसान जो पैदावार बढ़ाए, उसके लिए उसको ईनाम न दे कर उसकी सजा दी जाए। मालिक ईनाम देना भी चाहे तब भी मजबूर है, ईनाम के बजाए सजा मिल रही है।

राव साहब को मैं थोड़ी सी लगती हुई बात, खटकती हुई बात कहता हूं। राव बीरेन्द्र सिंह उम्र में कुछ बड़े हो गए और शेर कुछ दब गया। गरीब के लिए जो काम करेगा उनको उसकी कीमत भुगतनी होगी। दुनियां के जितने बड़े-बड़े आदमी हुए हैं उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है और उस वक्त की ताकत ने और समाज ने उनको सजा दी है। राव बीरेन्द्र सिंह जब हरियाणे के मुख्यमन्त्री थे तो इन्होंने एक छोटा सा काम किया था। किसानों को जौ का भाव, चने का भाव दिया था। सारे हिन्दुस्तान में तहलका मच गया था। शोषण करने वाले लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तकलीफ देने में लेकिन उस वक्त एक हिम्मत थी। राव बीरेन्द्र सिंह शायद अब उस ताकत वाले नहीं रहे।**

इजाजत के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अब वे खतरा मोल लेने की स्थिति में नहीं हैं। आप इसको कान में लगा लीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have heard. I can easily follow your Hindi. I am following.

श्री मनी राम बागड़ी : उपाध्याय महोदय, मेरा बुनियादी सवाल है। इस आलू के लिए तकलीफ आपको भी होती है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Bagri Sahib, don't you want me to learn Hindi from your Speech ? I can follow you.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : You can follow everybody.

(*Interruptions*)

श्री मनी राम बागड़ी : तकलीफ इनको भी होती है, लेकिन ये बेजुबान हैं, बोल नहीं सकते। बाजरे की सपोर्ट प्राइस है, सरकार ने सपोर्ट प्राइस मुकरर कर दी थी लेकिन आपके हुक्म के बावजूद भी क्या बाजरा खरीदा गया ? जवाब मिलेगा नहीं। आप ** कर कुछ नहीं सकते। अगर आप कोई बात नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए लेकिन गलत मत बोलिए। आलू को सिर्फ सब्जी मत कहिए। खुराक कहने की हिम्मत नहीं है तो इसको सिर्फ सब्जी मत कहिए। आलू भारत के अन्दर नहीं बल्कि दुनियां में, न सब्जी है न खुराक है। जरूरत पड़े तो सब्जी भी है और जरूरत पड़े तो खुराक भी है।

गरीब के लिए तो आलू खुराक और सब्जी दोनों ही है। भारत की प्रधान मन्त्री कहती हैं कि गेहूं, चावल न मिले तो केले खाओ। यह शायद अमीरों की बात है।.....

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रधान मन्त्री ने कभी नहीं कहा। आप, शायद फ्रांस की किसी मलिका की बात कर रहे हैं। यह आपके दिमाग की उपज है।

** Expunged as ordered by the Chair.

श्री मनी राम बागड़ी : अगर नहीं कहा तो बहुत अच्छी बात है। आलू दुनिया के सभ्य और मालदार मुल्कों की खुराक और सब्जी भी है। यह गरीब लोगों की हर सब्जी का एक अंग है। यहां पर दस किलो की बात की जाती है, लेकिन गरीब को तो उसके दर्शन ही नहीं होते। उसको तो हफ्ते में पेट भर कर रोटी भी नहीं मिलती, आलू की बात तो उसमें है ही नहीं। मैं पूछना चाहूंगा कि आलू कितना पैदा होता है, कितना होना चाहिए और कितना सरकार बढ़ाना चाहती है ? प्रान्तों और गांवों का एक संपर्क होता है। इसलिए प्रान्तों के माध्यम से आलू की पैदावार बढ़ाने की जिम्मेदारी राष्ट्र की है। आलू की पैदावार राष्ट्र नहीं बढ़ा सकता जब तक उसे पूरा सहयोग प्राप्त न हो। आप तो सिर्फ एक माध्यम हैं। अभी तक भारत सरकार निश्चित नीति और निशाने पर नहीं पहुंच सकी है कि भारत को कितना आलू पैदा करना चाहिए ? सरकार को इतना अनुमान नहीं है कि कम से कम और ज्यादा से ज्याद कितना होना चाहिए ? यह सरकार निकम्मी और पाजी है। अगर सरकार के पास आंकड़े हैं तो यह बताया जाए कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा इतनी पैदावार होनी चाहिए। यदि इतने से कम या ज्यादा हुआ तो उससे नुकसान होगा। दोनों तरफ से राष्ट्र को नुकसान होगा। पहली बात यह है कि क्या सरकार ने कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितनी पैदावार होनी चाहिए, इसका लक्ष्य निर्धारित किया है। यह गांधी का देश है, इस को यूरोप या अमेरिका नहीं बना सकते। दूसरी बात कोल्ड स्टोरेज के बारे में है। क्या सरकार सिर्फ बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाकर आलू की हिफाजत करना चाहती है ? क्या कोई छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाने का भी विचार है जिससे आलू खराब न हो ? कोल्ड स्टोरेज में कितने आलू रखने की कैपेसिटी है ? और कितना आपका बनाने का लक्ष्य है ? यह तो बड़े में रही। और छोटे धन्धे जो हैं, जो गान्धी जी का आदर्श था गांव के स्तर पर कुटीर उद्योग की तरह है, दिल्ली, कानपुर में न बना कर के, रेवाड़ी, रामपुर में या जहां नसीबपुर का मैदान था, ऐसी छोटी जगह में जहां आलू उत्पन्न होता हो, वहां कोल्ड स्टोरेज या ऐसे घर जिनके अन्दर किसान लोग अपना आलू रख सकें, बनाने का इरादा है ? अगर है तो बड़े कोल्ड स्टोरेजों में कितना लोग रख सकते हैं, क्या उनकी कैपेसिटी है और नए कोल्ड स्टोर बनाने का इरादा क्या है ? और दूसरे जो छोटे ढंग के कोल्ड स्टोर हैं, जैसी कि गान्धी जी की कल्पना थी, जिसमें 1,2,3 मन आलू किसान साल भर रख सकता है, ऐसे स्टोर बनाने की भी आपकी कोई नीति है ? यदि हां, तो वह क्या है, यह मंत्री जी बतायें।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान का नुक्सान एक चीज है, उससे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन राष्ट्र को जो नुक्सान होता है उससे बहुत तकलीफ होती है ; सस्ता आलू बिकता है तो किसान तबाह होता है, लेकिन आलू का सड़ जाना, फसल का बिगड़ जाना यह देश की सम्पत्ति की बरबादी है। किसान का तबाह होना बुरी बात है, लेकिन पैदा की हुई सम्पत्ति चाहे वह गेहूं हो या आलू, सड़ जाय तो उससे राष्ट्र को नुक्सान होता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, सारे भारतवर्ष में लाखों मन आलू सड़ गया और सड़ रहा है। आप कहें तो मैं अखबार की कटिंग्स दिखा सकता हूं, लेकिन उसमें समय लगेगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा क्या सरकार ने यह आंकड़े देश के अलग-अलग राज्यों से इकट्ठे करा के मांगे हैं कि कहां-कहां आलू सड़ गया, कितना सड़ गया और कितना सड़ने जा रहा है ? और जो सड़ रहे हैं उनको कैसे रोका जाय ?

आखिरी बात सब्जियों की है। आप सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे हैं यह कह कर कि यह फल है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप जानते हैं आलू फल नहीं है। और सब्जी होती है वह जिसके बगैर आदमी रोटी न खा सके। यह तो एक ऐसी चीज है जो बाबा जी के बाबा जी, और तरकारी की तरकारी जिसका नाम आलू है। आलू की सपोर्ट प्राइस नहीं कर सकेंगे, कोई कानूनी कठिनाई हो सकती हैं, मैं मानता हूं कि आपकी इतनी शक्ति नहीं है कि आप जो चाहें कर सकें क्योंकि इस पर तो कैबिनेट का डिसीजन होता है। और फिर यह तो ऐसा है कि एक आदमी किसान का फायदा चाहता है, तो दूसरा नुक्सान चाहता है। तो यह तो गणेश जी की बारात है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

तो सपोर्ट प्राइस न सही, लेकिन कम से कम 50 रुपए क्विंटल भी कोई कीमत है ? और अगर 8 आना किलो ही मुकर्रर करते हैं तो क्या यह गारन्टी कृषि मंत्री देने के लिए तैयार होंगे कि साल भर तक फिर उसकी कीमत 8, 10 आने किलो से ज्यादा नहीं होगी ? यह छोटी-छोटी बात है, बेचारी मालन रेड्डी पर बेचती है या दोनी बेचती है, उसको छोड़िए, वह 4, 5 रुपये से ज्यादा नहीं कमाती है।

यह थोक की बात है, लूट और शोषण की बात है। बुनियादी तौर पर हिन्दुस्तान की दाम नीति को समझने के लिए कि फसल खेत से निकल कर कल-कारखाने या उद्योग में जाने तक जो बीच में गैप है, उसको कभी लम्बा नहीं बनने दिया जाएगा, क्या इसके लिए आप कोई आश्वासन दे सकते हैं ? जैसे फसल के मौके पर क्या दाम है, उससे सवाया दाम से ज्यादा दूसरी फसल आने तक कीमतें न बढ़ सकें, क्या इतनी गारन्टी देने के लिए आप तैयार हैं ?

मैं कृषि मंत्री जी को किसान होते हुए भी सेठ कहना चाहूंगा। एक सेठ बिड़ला है और दूसरे सेठ राव बीरेन्द्र सिंह। लेकिन राव बीरेन्द्र सिंह सेठ नहीं, वह तो सिविल सप्लाई वाला सेठ है। खरीदने वाला आपका नाफेड है और बिड़ला साहब से भी ज्यादा डाका मारते हैं, उसका ज्यादा सम्बन्ध भागवत झा आजाद के महकमे से है। क्या इन चोरों को पकड़ने का कोई रास्ता है या ये बेकाबू हो चुके हैं ? ये मण्डी वालों से मिलकर ज्यादा मुनाफा लेकर ऊपर से नीचे तक जो काम चला रहे हैं, क्या इसे रोकने का कोई इलाज है ? जितना उचित समझें माननीय मंत्री जी जवाब दे सकते हैं लेकिन क्या ऐसा नहीं कि एक दो मिनट के लिए राव बीरेन्द्र सिंह जो कि लोगों के जौं के वास्ते खुद गर्दन कटवाना चाहते थे, अब कड़े नजरिये को थोड़ा ढीला करें और शेर की तरह बात करें ?

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय बागड़ी जी ने जो बातें कही हैं, उनका अहसास सरकार को है, मैं भी उनको महसूस करता हूं, लेकिन बागड़ी जी आजादी से कह सकते हैं और जो काम वह कहें, वह करना उनके जिम्मे नहीं है। सरकार को कुछ कहते वक्त सोचना पड़ता है कि हम यह कर भी पायेंगे ?

किसी चीज को इम्पलीमैंट करने के लिये हमारी बहुत सी कठिनाइयां हैं। सोचना पड़ता है कि किस हद तक यह पासिबल है कि कोई पालिसी बना लें और वह पूरी तरह लागू कर पायेंगे। एक बात कह दें, वादा कर लें, एश्योरेंस दे दें और वह बात पूरी न हो पाये तब क्या हो ?

सब्जी, फल, खुराक का बड़ा मसला है, यह मैं मानता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि

(राव बीरेन्द्र सिंह)

आलू को हम खुराक नहीं मानते। आलू बड़ी जरूरी खुराक है। यह गरीब आदमी के लिये आम चीज है और सब्जीखोर लोगों के लिए अच्छी तरकारी है, सब्जी है जिससे आदमी पेट भरकर थोड़े पैसों में रोटी खा सकता है। इससे कोई इन्कार नहीं कि आलू की पैदावार जितनी बढ़ रही है, उसको गिरने न दिया जाए, लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमने कोई लक्ष्य नहीं रखा है कि आलू जैसी चीज की हम कहां तक पैदावार बढ़ाना चाहते हैं।

मार्केट-फोर्सेज कितना किसान को लाभ देती हैं, क्या चीज बोकर किसान ज्यादा कमा सकता है, अगर उसको फायदा न हो आलू बोने में तो और बहुत सी चीजें हैं जिनकी पैदावार किसान उसी खेत में कर सकता है और बदले में दूसरी फसलें ले सकता है, यह चीज किसान पर ही छोड़नी पड़ती है।

हिन्दुस्तान ऐसा देश नहीं है जिसमें फील्ड लेवल तक की हम प्लानिंग कर सकें। खेत के लेवल पर प्लानिंग न सरकार करना चाहती है और न हम किसान को इस बात के लिये मजबूर करना चाहते हैं कि यह चीज तुम्हें पैदा करनी होगी। न यह चीज हम अनाज के लिये करते हैं और न दूसरी चीजों के लिये। हम किसान को मजबूर नहीं करना चाहते।

किसान आजाद है, वह जिससे ज्यादा फायदा उठाये, उसे पैदा करे, लेकिन जो पालिसी सरकार की है, उनमें हम जरूर यह कोशिश करते हैं कि ऐसी बात न होने दें कि किसी एक चीज की कमी हो जाए देश के अन्दर जैसे अनाज की और किसान ज्यादा कैश-क्राप पैदा करना शुरू कर दे।

मार्केट में कुछ वैलेंस रहे, इसके लिए सरकार जो कुछ कर सकती है, वह हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम किसानों पर कोई बात लादना नहीं चाहते। श्री बागड़ी इस बात से सहमत होंगे कि किसान को किसी बात के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसका दिल टूट जाएगा।

आलू के लिए चार-पांच साल से 7 लाख एकड़ से 8 लाख एकड़ का रकबा रहा है। उसमें कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, हालांकि आलू की पैदावार बढ़ी है। यह पैदावार अच्छे बीज की वजह से यील्ड पर यूनिट में इजाफा होने से बढ़ी है। अगर किसी साल बारिश ज्यादा होती और मौसम अच्छा होता है, तो किसान ज्यादा आलू बो देते है और साल में दो तीन फसलें हो जाती हैं। लेकिन आलू के रकबे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है।

किसान अपने घर में दो तीन मन आलू रख सके, यह कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन उससे समस्या हल नहीं होती। आलू उत्पादन करने वालों को सहायता तो तब मिलेगी, जब बड़ी-बड़ी कैपेसिटी वाले कोल्ड स्टोर हों, जिनमें किसान अपना आलू रख सकें और व्यापारी भी आलू खरीद कर उसमें रख सकें। अगर हम व्यापारियों पर ज्यादा पाबन्दी लगाएंगे, तो मार्केटिंग की जिम्मेदारी कौन सम्भालेगा ? हम चाहते हैं कि कोआपरेटिव सोसायटियां यह काम करें। इस लिये यहां पर कानून पास कर के नेशनल हार्टिकलचर बोर्ड बनाया गया है और उसका काम शुरू होने वाला है। हम चाहते हैं कि हम किसानों, कोआपरेटिव सोसायटियों, प्राईवेट इन्डस्ट्रीज और पब्लिक सैक्टर की इन्डस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा सहायता दें, ताकि उत्पादन करने वालों को चीजों की मुनासिब कीमत मिले।

सब्जियों और फलों के सड़ने से कितना नुक्सान होता है, इसका स्टेटवाइज अन्दाजा मेरे पास नहीं है और न ही यह लगाया गया है। अन्दाजा यह है कि हिन्दुस्तान में सब्जियों और फलों की कुल पैदावार 50 मिलियन टन है, और जहां तक मुझे याद पड़ता है, उसमें से 14 परसेन्ट के करीब गल-सड़ कर खराब हो जाते हैं। यह 14 परसेंट नुकसान हमारे लिये बहुत ज्यादा है। इसका नुकसान उत्पादक को होता है, न यह उपभोक्ता के पास पहुंचता है और न एक्सपोर्ट हो पाता है। हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

आम किसान के लिये इन चीजों को ठीक हालत में रखने के कई तरीके हैं। इण्डियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने पूसा इन्स्टीट्यूट में एक नुमाइश की थी। अगर श्री बागड़ी ने उसे देखा होता, तो अच्छा होता। उसमें देशी किस्म का किसान का अपना रेफ्रिजरेटर था, जो दो तीन सौ रुपए में बनाया जा सकता है। दो ईंट की पतली तह लगा कर उस में जमुना की सैंड भरी हुई थी। चार छः इन्च जगह छोड़ दी गई थी, वैक्यूम हो गया और ऊपर खस की ट्टी लगा दी गयी, जिस पर दिन में एक दो बार छिड़काव किया जाता था। उस में दो तीन मन सब्जी रखी जा सकती है। मैंने खुद देखा है कि तीन महीने पहले के संतरे, मौसमी और गाजर बिल्कुल ताजा नजर आते हैं। अगर किसान ऐसे तरीकों को अपनाए, तो बहुत थोड़ा पैसा खर्च करके वह दो तीन मन आलू अपने पास रख सकता है। ये चीजें बतायी जाती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ज्यादा जरूरत इस बात की है कि कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़े। उस के लिये कुछ कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं, कुछ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से स्कीमें हैं। सरकार तो बढ़ावा देना चाहती है। कुछ लोगों का इनीशिएटिव भी इस में चाहिए। इस में इन्डस्ट्री भी आगे आ रही है। इन्डस्ट्रीअलिस्ट्स लगा रहे हैं, कोआपरेटिव्ज भी बना रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों से दरख्वास्त की, अपने-अपने इलाकों में जहां आलू ज्यादा पैदा होता है वहां आप ज्यादा कोआपरेटिव लगवाइए प्रोसेसिंग प्लांट्स और लगवाइए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है सरकार के किसी लेवेल पर तो आप मुझे बताइए, मैं पूरी सहायता करने के लिए तैयार हूं।

श्री मनी राम बागड़ी : जिन कमजोर किसानों का आलू सड़ गया और जिन को नुकसान हुआ है उन को क्या सरकार सब्सिडी देने के लिए तैयार है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : पहली बात तो यही मेरी समझ में नहीं आ रही है कि कमजोर किसान का आलू सड़ गया। कमजोर किसान का मतलब छोटा किसान जिस में यह शक्ति या क्षमता नहीं है कि वह ज्यादा कीमत के इन्तजार में अपनी फसल को रोके दो महीने तक और बेचे न। आलू तो एक ऐसी फसल है, कैश क्राप कहलाती है, खोदते ही छोटा किसान और गरीब आदमी तो फौरन ही मंडी में फेंकता है चाहे उस को आठ आने किलो ही कीमत क्यों न मिले और दूसरे चाहे उस को जितनी ऊंची कीमत पर क्यों न बेचें ? जितनी इन चीजों की अर्ली वेराइटी होती है, आम फसल के वक्त से पहले जो तैयार हो जाएगी उस की कीमत ज्यादा मिलती है।..... (व्यवधान).....
मैं भी किसान हूं और छोटा ही हूं और इसलिए छोटे किसान की भी बात और बड़े किसान की भी बात मुझे मालूम है। किसान के मामले में मेरा यह कहना है, आप शायद ऐग्री करेंगे या हो सकता है कि आप को एतराज हो, मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह बहुत गलत

(राव बीरेन्द्र सिंह)

धारणा देश के अन्दर चल रही है जिस में किसान का हित नहीं है जो यह छोटे और बड़े किसान की बात की जाती है। सीलिंग लगने के बाद, कानून बनने के बाद, यह दूसरी बात है कि कहीं कानून पर अमल न हुआ हो और उस के अन्दर कहीं रुकावट हो लेकिन अगर ये लैंड लाज पूरी तरह से इम्पलीमेंट हों तो कोई बड़ा और छोटा किसान हिन्दुस्तान में नहीं है। एक दो जनरेशन के बाद हर एक किसान एक-एक दो-दो एकड़ का मालिक हो जाएगा जिस तरह से बच्चों के बीच में जमीन की तकसीम होती है और कोई बड़ा किसान भी अगर आज के दिन है तो वह खेती की पैदावार के ऊपर कोई पूँजीपति नहीं बन सकता, यह मेरा पक्का विश्वास है। जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं वह किसान के बारे में कुछ नहीं जानते, उन को खेती के बारे में कुछ नहीं पता कि किस तरह से खेती होती है और किसान को क्या दिक्कतें होती हैं। इस में यह बहुत छोटा किसान, बीच का किसान और बड़ा किसान, इस में अलग-अलग सब्सिडीज में भी फर्क है और-और चीजों में भी है इसलिए कि छोटे का मतलब हो जाता है कि सब से पूअरेस्ट जिस को कि अटेंशन सबसे पहले दी जाती है। छोटे की तरफ सरकार का ध्यान ज्यादा जाता है, स्माल और मार्जिनल फार्मर की तरफ, वैसे खेती में कठिनाई सब की बराबर है, दिक्कतें सबकी बराबर हैं और कोई आदमी किसान हो, खाली खेती पर गुजारा करता हो जैसे मेरा गुजारा है, खेती के अलावा मेरी कोई और पैसे की आमदनी नहीं है। पैसे का कुछ सूद आ जाय वह दूसरी बात है, लेकिन न दूकान है, न तिजारत है न किराया है मकान का न कुछ और है। तो मैं जानता हूं कि जाती तौर पर कि कितनी भी खेती आदमी करे वह उसके अन्दर पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता, उस के द्वारा वह पूँजीपति नहीं बन सकता। जो किसान भी हैं और व्यापार भी करते हैं वह बड़े किसान अगर आप की नजर में हों और पूँजीपति हों तो वह पूँजीपति खेती की अमदनी से नहीं, बल्कि अपनी दूसरी आमदनी की वजह से हैं जो उन्होंने जगह-जगह से पैदा की हैं।

श्री मनी राम बागड़ी : सब्सिडी का नहीं बताया।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : नहीं दे सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने काफी विस्तार से जवाब दिया होगा। मैं तो देर से आया हूं। फ्लाइट जो साढ़े ग्यारह बजे आती है वह अभी अभी पहुंची है। आपकी बड़ी कृपा है कि आप ने मुझे एलाऊ कर दिया।

मैं दो तीन बातें सरकार से जानना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि अभी राव साहब कह रहे थे आप लोग इस बात पर प्रोत्साहन लोगों को दीजिए कि अधिक से अधिक कोआपरेटिव सोसाइटी किसान बनावें और उसमें जो दिक्कत हो कोल्ड स्टोरेज को बनाने में उस दिक्कत को सरकार दूर करेगी। कोल्ड स्टोरेज में भी कम धांधली नहीं होती है। कोई गरीब आदमी उसके मालिक नहीं हैं। कोल्ड स्टोरेज वालों की मनोवृत्ति मुनाफा कमाने की ही रहती है। आपने बिहार में आलू की सपोर्ट प्राइस 50 रु० रखी है लेकिन हजारी बाग में आलू चार आने किलो बिक रहा है। दो साल पहले आलू की कीमत इसके मुकाबले आठ गुने थी जबकि दो साल पहले किसान की खुर्पी, औजार और दूसरी चीजों की जो कीमतें थीं उसके मुकाबले

आज डढ़े गुनी हो गई है। चूंकि किसान के पास जवान नहीं है इसीलिए उसका शोषण हो रहा है।

कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक हैं, वे मनमाने रेट फिक्स कर देते हैं। सारे देश में कोल्ड स्टोरेज का एक जैसा रेट नहीं है। यह बात भी सही है कि बिजली की आपूर्ति ठीक प्रकार से न होने के कारण कोल्ड स्टोरेज की हालत भी खराब रहती है। मैं जानना चाहूंगा कि अपने स्तर पर सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज बनाने का विचार है या नहीं ? यदि है तो कितने और इस समय सरकार द्वारा कुल कितने कोल्ड स्टोरेज चलाये जा रहे हैं। जो प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज हैं उनको क्या सरकार अपने अधीन करने की बात सोच रही है या नहीं।

आलू की खेती पंजाब में भी होती है और इस समय पंजाब की हालत बहुत खराब है। वहां पर किसानों के पास आलू होगा लेकिन व्यापारी वहां पर जाना नहीं चाहेंगे तो पंजाब के किसानों के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे ?

यहां पर नाफेड की चर्चा आई होगी और शायद आपने बताया होगा कि नाफेड के कितना आलू पर्चेज करने में सक्षम रहा है। यदि नहीं बतलाया है कि कृपा करके आप बतलाइयेगा कि नाफेड के द्वारा कितने आलू की पर्चेज की गई है ? साथ ही यह भी बताइयेगा कि सरकारी स्तर पर आप कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात सोच रहे हैं या नहीं ? इसके अलावा सरकार किसानों से आलू की खरीद नाफेड के द्वारा करती है। यू. पी. की एक और संस्था है जिसके द्वारा किसानों का आलू खरीदा जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि इन दो संस्थाओं के अलावा भी क्या और भी कोई संस्था है जिसके द्वारा सरकार आलू किसानों से खरीदने और उनका घाटा पूरा करने का काम करती है ?

जैसाकि आप जानते हैं आलू की फसल बड़ी नाजुक होती है। अगर पाला पड़ जाये या ओला पड़ जाए तो आलू की फसल समाप्त हो जाती है। इसी तरह से कोल्ड स्टोरेज में चाहे साल भर बिजली की सप्लाई ठीक रहे लेकिन अगर पांच दिन के लिए ही बिजली की सप्लाई बंद हो जाए तो वहां पर सारा आलू सड़ जायेगा। जब कभी खाद्यान्न की कमी हो जाती है तो सरकार आलू खाने की सलाह देने लगती है और कहती है कि आलू बड़ा पुष्टिकारक होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आलू की फसल के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कम्पेन्सेशन देने की भी योजना है या नहीं। साथ ही आलू को एक्सपोर्ट करने की क्या व्यवस्था है, यह भी मैं सरकार से जानना चाहूंगा। अगर जरूरत से ज्यादा आलू की पैदावार हो जाये तो उसकी आप एक्सपोर्ट करने की अनुमति देते हैं या नहीं और इसके लिए क्या कोई नियम हैं, यह भी बताने की कृपा करें।

राव बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें माननीय सदस्य ने उठाई हैं, उन सब का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। पासवान जी ने करीब-करीब वही बातें कहीं हैं। पासवान जी ने कोल्ड स्टोरेज के बारे में कहा है।

श्री राम विलास पासवान : अभी तक सरकार द्वारा कितने कोल्ड स्टोरेज कायम हुए हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हम चाहते हैं कि ये बढ़े। सरकार अपने कोल्ड स्टोरेज लगाए, यह मुमकिन नजर नहीं आता है।

श्री राम विलास पासवान : क्यों ?

राव बीरेन्द्र सिंह : वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन की तरफ से बन रहे हैं। जो सरकार की एजेंसी है।

श्री राम विलास पासवान : कम हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कम हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। कोआपरेटिव्ज के जरिए से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज बनवायें। मैं यही बात कर रहा था आपके आने से पहले। कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए हम पूरी सहायता देने के लिए तैयार हैं। एन. सी. डी. सी. से कम सूद पर पैसा मिल सकता है। रूरल डवेलपमेंट मिनिस्ट्री के रूरल वेयर हाउसिंग की स्कीम अलग है उसके अधीन कोल्ड स्टोरेज और भी लगा सकते हैं। प्राइवेट इन्डस्ट्री भी लगा रही हैं। लेकिन सरकार डायरेक्टली कोल्ड स्टोरेज बनाए और चलाए यह मुमकिन नजर नहीं आता है। सरकार की एजेन्सीज हैं, जो बना रही है। स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन भी हैं। सैन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन भी है।

14.01 hrs.

(SHRI N.K. SHEJWALKAR *in the Chair*)

दूसरी बात आपने एक्सपोर्ट के बारे में कही है, जिसके बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूं। ओ. जी. एल. के थ्रू एक्सपोर्ट की खुली छूट है। इसके लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते है कि एक्सपोर्ट बढ़े और ज्यादा से ज्यादा बढ़े। लेकिन मैं कठिनाइयां पहले ही बता चुका हूं। इन्टरनेशनल प्राइस कम होते हैं। हिन्दुस्तान में एक्सपोर्ट करने से व्यापारियों को कोई लाभ नहीं होता है।

श्री रामावतार शास्त्री : लेकिन दाम न बढ़ने दीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं, कंज्यूमर का भी ध्यान रखना पड़ता है। खुराक की दृष्टि से भी इतना बढ़ने पाए। दूसरी बात बिहार में भाव कम होने की बताई गई और कुछ पंजाब का भी जिक्र किया गया। हमारे पास अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। बिहार की मंडियों में 50 रु० क्विंटल से कम भाव हैं।

श्री राम विलास पासवान : हजारी बाग में चार आने है।

राव बीरेन्द्र सिंह : न पंजाब की मंडियों से और न कहीं से अभी तक इत्तला मिली है कि इतने भाव गिर गए हैं, जितना कि आप बता रहे हैं। यदि है, तो उसको चैक कर लिया जाएगा। राज्यों की तरफ से हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। लेकिन जहां पर कभी भाव 50 रु० से नीचे गिरेगा, वही पालिसी अपनाई जाएगी। यू. पी. के मामले में नाफेड और यू.पी. सरकार की एजेंसियां खरीदना शुरू कर देंगी और 50 रु० से भाव नीचे गिरने नहीं देंगी। पंजाब से कोई इत्तला नहीं आई है, इसका मतलब यह है कि वहां भाव अच्छे चल रहे हैं। नेशनल कन्ज्यूमर कोआपरेटिव फडैरेशन सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है। उसका भी यही काम है कि किसान की जो पैदावार हो, उसको खरीदे और जहां कहीं भाव अच्छे हो, दूसरी मंडियों में, वहां भेजे। हमारे पास दो एजेंसियां हैं, जिनके जरिए भारत सरकार काम कर रही है।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Sir, the Minister has not

replied to one point. It is not out the percentage of people having sugar—this applies to most of the ruling party members—it is because they are consuming less potatoes and this is also one of the reasons for the potatoes prices having come down.

राव बीरेन्द्र सिंह : जिसकी सेहत जितनी इजाजत दे ज्यादा से ज्यादा उतना लेना चाहिए। डायट का बैलेंस तो रखना ही पड़ता है। चावल भी ज्यादा नहीं खा सकते हैं, वह भी आलू की तरह से खराब करता है।

श्री रामावतार शास्त्री : आप लोग कम खाते हैं, हम लोग ज्यादा खाते हैं।

14.04 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

National oilseeds and Vegetable oils Development Board

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : Sir, I beg to move the following :—

"That in pursuance of sub-section (4) (e) of Section 4 of the National Oilseeds and vegetable Oils Development Board Act, 1983, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the National Oilseeds and vegetable Oils Development Board, subject to the other provisions of the said Act."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That in pursuance of sub section (4) (e) of Section 4 of the National Oilseeds and vegetable Oils Development Board Act, 1983, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

14.06 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) *Need to give clearance to Mahanadi Chitrotpala irrigation project*

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Cuttack) : Extension of irrigation potential of Mahanadi Chitrotpala island, Orissa has been planned to be taken up in two phases. The project report for the first phase to provide irrigation to Mahanadi Chitrotpala island has been prepared and submitted to the Central Water Commission in December, 1982 for technical scrutiny and approval of Planning Commission. The estimated cost of the project is Rs. 19.46 crores. It is regrettable that the planning Commission has not yet given clearance for the execution of this irrigation project.

The completion of this irrigation project will create irrigation potential of 15342 hectares of Kharif crops and 11507 hectares of Rabi crops in Mahanadi - Chitrotpala island in Orissa. The farmers of the State of Orissa have been facing great difficulties in the absence of irrigation facilities. There fore it is necessary to execute the above irrigation project during the current plan period.

I request the concerned Minister to lay greater emphasis on this project and direct the Central Water Commission to clear this project at an early date. The second phase should also be cleared by Central Water Commission along with the first phase proposal of the Mahanadi - Chitrotpala irrigation project.